भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1216

दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

1216. श्री नवसकनी के.:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह योजना तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढाने और गरीबी उपशमन में प्रभावी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य में इस योजना के आरंभ से इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीईडीएस के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत/उपयोग की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार सृजित करने और अवसंरचना प्रदान करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार इस योजना के लिए और अधिक निधियां आवंटित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) सितंबर, 2010 से मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थी। इस योजना के तहत देश में 4,21,158 लाभार्थियों को बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में कुल 1892.29 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई। डीईडीएस को दिनांक 01.04.2020 से बंद कर दिया गया है।

(ग) राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों और डीएएचडी, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/पहलों के अलावा, डीईडीएस ने भी तमिलनाडु में दूध उत्पादन को वर्ष 2009-10 के 6.787 एमएमटी से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में 8.795 एमएमटी करने में योगदान दिया था। डीईडीएस की शुरूआत के बाद से अब तक तमिलनाडु में 66961 लाभार्थियों को 129.03 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) चूंकि डीईडीएस को दिनांक 01.04.2020 से बंद कर दिया गया था, इसलिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि संस्वीकृत नहीं की गई।

(ङ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करते हुए, डीएएचडी, भारत सरकार डेयरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार सृजित करने और अवसंरचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन- इसका उद्देश्य देशी बोवाईन नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाईन संख्या का आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईनों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है।

ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना तथा संगठित दूध खरीद के हिस्से को बढ़ाना।

iii. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: अन्य के साथ-साथ दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना का सृजन/आधुनिकीकरण।

iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता: कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज सबवेंशन के रूप में सहायता प्रदान करना।

इसके अलावा, सरकार ने पशुपालन और डेयरी किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा भी प्रदान की है।

(च) उपरोक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

****